



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 322]

नई विल्सी, सोमवार, जून 29, 1987/आषाढ़ 8, 1909

No. 322]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1987/ASADHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रधान)

नई दिल्ली 29 जून, 1987

अधिसूचना

का. आ. 646 (अ) —केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विभागमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) द्वी प्रधान 6 की उपचारा (1) के खण्ड (ण) द्वारा प्रवत्त ग्रन्तियों का प्रयोग करते हुए, एक "पारस्परिक निधि" बढ़ा करने अथवा स्थापित करने और संचालित करने का इस प्रकार का कारबाह विनियोग करती है, जिसको करना बैंककारी कामनी के लिए विधिमत्त है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए—

(क) "पारस्परिक निधि" से अधिवेत है—

(i) प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंध, व्यापार या व्यवस,

सहभागिता प्रमाण-पत्र या किसी अन्य लिखत का कारबाह;

(ii) धार्य और वृद्धि का सहभागिता कारबाह;

(iii) युनिट ट्रस्ट स्कीम,

जो उनसे उद्भूत होने वाली धार्य, लाभों या अधिलाभों में सहभागिता निया, सहभागी सदस्यों को शेयरों या यूनिटों के द्वारकों के रूप में या अन्यथा, इस प्रयोजन के लिए सूचित किसी निधि की मुद्रिधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए है।

(ब) "यूनिट ट्रस्ट स्कीम" से प्रतिसूतियों या सभी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण प्रबंध या व्ययन से उद्भूत होने वाले लाभों या धार्य में किसी न्यास के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सहभागिता के निए सुविधाएं देने के प्रयोजन के लिए किए गए कोई छहराव अधिवेत हैं, या जिनका प्रधान प्रतिसूतियों या सभी प्रकार की अन्य सम्पत्ति के अर्जन, धारण, प्रबंध या व्ययन से उद्भूत होने वाले लाभों या धार्य में किसी न्यास के अधीन हिताधिकारियों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सहभागिता के लिए सुविधाएं देना है।

(ग) "प्रतिभूति" के अंतर्गत है—

(i) किसी कमनी या अन्य नियमित विकाय के शेयर,

डिमेंचर, बंधपत्र, लिखते और अन्य स्टाक;

- (ii) कम्पनियों, अन्य निगमित निकायों, अनुसूचित बैंकों या क्रिया-शील संस्थाओं में धन की निवेदन करता;
- (iii) केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी विदेशी सरकार या विदेशी बैंक या भारत के बाहर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आँख किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी वाणिज्यिक प्रपत्र या प्रतिभूति में विविधान;
- (iv) लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में परिभाषित सखारी प्रतिभूतियाँ।

[सं. 11/17/87-भी. घो.-III]
मनोज चन्द्र मस्तावी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 29th June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 646(E).—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (1) of section 6 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies setting up or establishing and conducting a "Mutual Fund" as a form of business in which it is lawful for a banking company to engage.

Explanations :—For the purposes of this Notification,—

(a) "Mutual Fund" means,—

- (i) the business of acquisition, holding, management, trading nor disposal of securities, participation certificates or any other instruments;

- (ii) income or growth participation business;
- (iii) unit trust schemes;

for the purpose of providing facilities for participation in, or distribution of, the income, profits or gains arising therefrom to the participating members as holders of shares or units or otherwise, of any fund created for the purpose.

(b) "unit trust scheme" means any arrangements made for the purpose, or having the effect, of providing facilities for the participation by persons, as beneficiaries under a trust, in profits or income arising from the acquisition, holding, management or disposal of securities or any other property whatsoever.

(c) "securities" include—

- (i) shares, debentures, bonds, instruments and other stock of any company or corporate body;
- (ii) keeping money on deposit with the companies, other bodies corporate, scheduled banks or like institutions;
- (iii) investments in any commercial paper or security floated by the Central Government, the Reserve Bank of India or any local authority, or by any foreign Government or foreign bank or any other authority outside India and approved by the Reserve Bank of India; and
- (iv) Government securities as defined in the Public Debt Act, 1944(18 of 1944).

[No. 11/17/87-BO-III]

M. C. SATYAWADI, Jt. Secy.